मेथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल से चलेंगी गाड़ियां!

पेट्रोल बिल में मंथली 10% की आएगी कमी, क्रूड ऑयल का आयात घटेगा

[योगिमा सेठ शर्मा & रजत अरोड़ा]

नीति आयोग चाहता है कि 15 पर्सेंट मेथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल से देश में गाड़ियां चलें। वह इसे अनिवार्य बनाने के लिए एक कैबिनेट जल्द नोट लाएगा। अगर इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो इससे पेट्रोल बिल में मंथली 10 पर्सेंट की कमी आएगी और कच्चे तेल के आयात पर सरकार को काफी बचत होगी। जुलाई के आखिरी हफ्ते में इस पर चर्चा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। एक बड़े सरकारी अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट सेक्रेटरी पी के सिन्हा खुद इस मामले में प्रगति पर नजर रखे हुए हैं।

नीति आयोग ने 'मेथेनॉल इकनॉमी' का एक रोडमैप बनाया है। इसमें साल 2030 तक कच्चे तेल के आयात पर खर्च में सालाना 100 अरब डॉलर की कटौती की बात कही गई है। आयोग ने कहा है कि 15 पर्सेंट ब्लेंडेड फ्यूल को अपनाने पर ही यह संभव होगा। अभी देश में 10 पर्सेंट तक एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बेचने की इजाजत है। एथेनॉल की कीमत अभी 42 रुपये प्रति लीटर है, जबकि मेथेनॉल का दाम 20 रुपये प्रति लीटर से भी कम रहने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में पेट्रोल में 15 पर्सेंट मेथेनॉल मिलाने पर पेट्रोल के दाम में 10 पर्सेंट की कमी आएगी। इस प्रस्ताव पर ऑटो इंडस्ट्री ने संभलकर प्रतिक्रिया दी है।

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के डायरेक्टर जनरल विष्णु माथुर ने कहा, 'इंडस्ट्री को पहले यह देखना होगा कि इसके लिए इंजन में कितना बदलाव करना होगा। आज चार पहियों वाली जो भी गाड़ियां बन रही हैं, उनमें 18-20 पर्सेंट तक ब्लेंडेड फ्यूल का इस्तेमाल हो सकता है। यह एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल के लिए है।'

ET कमेंट

2030 तक कच्चे तेल के आयात पर खर्च में सालाना 100 अरब डॉलर की कटौती के मकसद से मेथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रस्ताव आकर्षक है। इसके लिए मेथेनॉल की उपलब्धता और ब्लेंडेड फ्यूल के लिए इंजनों में बदलाव पर गहराई से विचार करना होगा।

नीति आयोग का प्लान

- नीति आयोग ने पेट्रोल में 15% मेथेनॉल मिलाने का प्रपोजल तैयार किया है
- मेथेनॉल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर डीजल में भी मिलाया जा सकेगा
- मेथेनॉल की लागत ₹20 प्रति लीटर से भी कम आएगी
- मेथेनॉल का प्रॉडक्शन कोयले से किया जाएगा
- ब्लेंडिंग से कम से कम 10% घटेगी पेट्रोल की लागत
- ब्लेंडेड M-15 फ्यूल के लिए इंजन में थोड़ा चेंज करना होगा
- 2030 तक फ्यूल इंपोर्ट बिल में आएगी $100 अरब कमी

Economic Times
3/8/2018